देश की जनता पर
ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमलों की प्रतिबिंब ही है
'समाधान' की दमनकारी रणनीति!
जनता की बुनियादी समस्याओं की हल के लिए
शोषक-शासक वर्गों के पास
'समाधान' के सिवा और कुछ नहीं!
इस फासीवादी 'समाधान' का प्रतिरोध करें व हराएं!

25-31 जनवरी के बीच 'समाधान' हमले के खिलाफ
देशभर में विरोध सप्ताह और
31 जनवरी को भारत बंद का सफल बनाएं!

केंद्रीय कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

देश की जनता पर
ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमलों की प्रतिबिंब ही है
'समाधान' की दमनकारी रणनीति!
जनता की बुनियादी समस्याओं की हल के लिए
शोषक-शासक वर्गों के पास
'समाधान' के सिवा और कुछ नहीं!
फासीवादी 'समाधान' का प्रतिरोध करें व हराएं!

प्रिय जनता!

हमारे देश की जनता को 20 महीने के पहले समाधान की रणनीति के बारे में परिचय हुआ। यह रणनीति अपनी समस्यओं की हल के लिए किसी एक समाधान निकालेगी, इस तरह की धोखा या भ्रम जनता के अंदर फैलाने की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन, इस देश के माओवादी आंदोलन के इलाके के जनता 'समाधान' के बारे में भलीभांति जानते हैं। इसी तरह, हमारा देश के केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लागू जनविरोधी नीतियों के बारे में समझ रखने वालों की भी 'समाधान' के बारे में जानकारी है। इस अवसर पर 'समाधान' द्वारा किये जा रहे विध्वंसकारी और विनाशकारी कार्रवाइयों के बारे में जानेंगे। उसमें जाने से पहले केन्द्र सरकार द्वारा रेखांकित 8 अक्षर की संक्षिप्त नाम 'समाधान' (SAMADHAN) में छिपी हुई गहरी अर्थ के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि, शासक वर्गों की उसकी जरूरत के बारे में और उससे संघर्ष करने की आवश्यकता के बारे में जानेंगे।

अंग्रेजी अक्षरमाला में 8 अक्षर की संक्षिप्त नाम 'समाधान' का विस्तारित व्याख्या निम्न प्रकार है :

S - Sharp Leadership (सक्रिय नेतृत्व)

A - Agressive Strategy (आक्रामक रणनीति)

M - Motivation & Training (प्रेरणा एवं प्रशिक्षण)

A - Actionable Intelligence (कार्रवाई योग्य सुचनातंत्र या निगरानी)

D - Dashboard Based Indicator (डैशबोर्ड आधारित संकेतक)

H - Hornessing Technology (तकनीकी ज्ञान को विकसित करना)

A - Action Plan For Each Threat (हर खतरे के लिए उपयुक्त कार्ययोजना)

N - No Access To Financing (आर्थिक स्रोतों की रोकथाम)

इस 'समाधान' हमला एक प्रतिक्रियावादी युद्ध रणनीति है। 50 साल पहले हमारे देश में उभरी नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान बगावत से लेकर 2017 तक केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए लागू किये गये कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीतियों में नई है यह 'समाधान' रणनीति। 'समाधान' रणनीतिक का सारांश यह है कि बहुत ही सक्षम नेतृत्वकारी शक्तियों का, अत्यंत आधुनिक प्राद्योगिकी (टेकनोलोजी) का और समस्त संसाधनों का प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अगले 5 सालों के अंदर देश में क्रांतिकारी आंदोलन को जड़ से उखाड़ कर उन्मूलन करना। क्रांतिकारी आंदोलन को उखाड़ने के बाद माओवादी-विहीन, भ्रष्टाचार-विहीन जाति और धर्म की भेदभाव-विहीन 'नया भारत' (न्यू इंडिया) का निर्माण करना हिन्दुत्व ताकतों की वैकल्पिक कार्यक्रम है। देश की जनता को याद होगा कि एक दशक पहले 2003-04 में एनडीए सरकार द्वारा 'शाइनिंग इंडिया' नारा दिया गया था।

नक्सलबाड़ी जनबगावत बहुत ही कम समय में 1960 दशक के अंत तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभर में विस्तारित हुई। उस आग को पूरी तरह बुझाने के लिए भारत की शोषक-शासक वर्गों द्वारा पहली बार लागू सैनिक अभियान की रणनीति थी 'ऑपरेशन स्टापिलचेज'। लेकिन वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पायी। देश के अंदर आपतकाल (जून 1975 से फरवरी 1977 तक) के बाद नक्सलबाड़ी की लपटें दावानल की तरह फैलते हुए नयी कार्यनीति के साथ देशभर में लहरों की तरह विस्तारित हुईं। वह 1979 दशक के अंत तक बिहार, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में जनता को क्रांतिकारी आंदोलन में गोलबंद किया। 1980 से लेकर अभी तक बीते चार दशकों की समयकाल को देश के अंदर नवजनवादी क्रांति की परचम को ऊंचा उठाने वाले समयकाल के रूप में और प्रतिक्रियावादियों के सामने कई चुनौतियां रखते हुए, कई ज्वार-भाटों को, उतार-चढ़वों को, टेढ़े-मेड़े रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ने वाली समयकाल के रूप में जाना जाता है।

इस पूरी समय में भारत की शोषक-शासक वर्गों द्वारा साम्राज्यवाद का दासता करते हुए, भारत की अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती लुटेरी व्यवस्था

को यथावत जारी रखने के लिए लागू किये गये सभी जनविरोधी और देशद्रोही नीतियों के खिलाफ देश में सच्ची आजादी, स्वालंबन और जनवाद की स्थापना के लिए देशभर में जनांदोलन हुए। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने देश के अंदर नवजनवादी क्रांति के सफल बनाने के लक्ष्य से दीर्घकालीन लोकयुद्ध का नेतृत्व करने के साथ-साथ उन जनांदोलनों में से कुछ एक को प्रत्येक्ष रूप से या तो नेतृत्व प्रधान किया या परोक्ष रूप से मदद पहुंचायी। इस दौरान हमारे पार्टी ने देश के अंदर एक वैकल्पिक जनशक्ति के रूप में उभर कर उत्पीड़ित जनता को - मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग और देशी पूंजीपति वर्ग को भरोसा दिलाया। इसका बर्दास्त न करने वाले साम्राज्यवादियों के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और बड़ा सामंतियों वर्गों ने 2005 में घोषणा की कि हमारे पार्टी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

पिछले 50 सालों में साम्राज्यवादियों की देखरेख में देश की शासक वर्गों द्वारा हमारे पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह उखाड़ने के लक्ष्य से 'ऑपरेशन स्टापिलचेज' से लेकर वर्तमान 'समाधान' हमले तक कई रणनीतिक चौतरफा अभियानों को एक के बाद एक लागू किये गये। उसमें सापेक्षिक तौर पर अधिक समय चली और अत्यंत विनाशकारी थी 'ऑपरेशन ग्रीनहंट'। वह लगभग 8 साल (अगस्त 2009 से लेकर अप्रैल 2017) तक जारी थी। केन्द्र व राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा लागू किये गये उन दमनकारी अभियानों के साथ-साथ राज्य प्रायोजित कई प्रतिक्रियावादी निजी सामंती सेनाओं और गुंडे तत्वों द्वारा जनता, जनहितैषी और क्रांतिकारियों पर कई हमलों को अंजाम दिये गये। हत्याओं, दंगों, विध्वंस, अत्याचार, घरों में आगजनी, फसलों को नष्ट करना, जहर देना आदि के जरिए आंदोलन को नुकसान पहुंचाया गया और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त किया गया। 'जनजागरण', 'शांति यात्रा जैसे अभियान कुछ महीनों तक चलाये गये, जबकि 'सलवा जुडूम', 'संद्रा' जैसे अभियान सालों तक (2005 से लेकर 2009 तक) संचालित किये गये। हमारे पार्टी के नेतृत्व में जनता ने प्रतिरोध युद्ध-जनयुद्ध जारी रखकर उस तरह के कई प्रतिक्रियावादी और विश्वासघातक निजी सामंती सेनाओं, गुंडे तत्वों और अभियानों को हराया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को यह आदेश देना पड़ा कि राज्य द्वारा जनता के बीच गृहयुद्ध पैदा करना, प्रोत्साहन करना और सभी तरह के मदद पहुंचाना गलत है।

लेकिन राज्य प्रत्येक्ष रूप से अपने सशस्त्र बलों को तैनात कर लागू किये

जाने वाले ऑपरेशनों और अभियानों के साथ-साथ गैर-राज्यीय तत्वों (नॉन-स्टेट एक्टर्स) को प्रोत्साहित कर क्रांतिकारी आंदोलन पर हमला करना दिन-ब-दिन बढ़ते गए। ऑपरेशन ग्रीनहंट में और वर्तमान 'समाधान' हमले में भी ये विस्तृत रूप ले लिया। एक तरफ क्रांतिकारी शक्तियों और दूसरी तरफ प्रतिक्रांतिकारी शंक्तियों; एक तरफ उत्पीड़ित जनता व जनहितैषी शक्तियों और दूसरी तरफ शोषक-शासक वर्गों, उनकी प्रतिनिधित्व करने वाली जनविरोधी सरकरों व उनकी सुरक्षा बलों; एक तरफ गरीब कमजोर वर्गों और दूसरी तरफ धनाढ्य व बल-सम्पन्न - स्पष्ट है कि शोषकों और उत्पीड़ितों में विभाजित एक वर्ग समाज में उन दो वर्गों बीच इस तरह की वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा देश में संविधान, संसदीय जनवाद झूठा और नाम मात्र ही है, यह सिर्फ दलाल नौकरशाह पूंजीपति और बड़ा सामंती वर्गों के तानाशाह के बजाए और कुछ नहीं है।

ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत शोषक-शासक वर्ग के सरकारों द्वारा एक तरफ लगभग साढ़े पांच सौ लाख अर्धसैनिक बल, कमांडों और विशेष पुलिस बलों को तैनात कर भारी दमनकारी ऑपरेशनों को अंजाम दिये जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जितने भी सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने के बावजूद, न सिर्फ जनता, ग्राम सभाओं और क्रांतिकारी जन कमेटियों (आरपीसी) ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट की अनुमति देने से इंकार किया, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के लूट के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके की जनता ने हमारी पार्टी के नेतृत्व में दृढ़ता से खड़े होकर संघर्ष किया। खदानों, इस्पात व थर्मल पावर प्लांटों, भारी बांधों, अभयारण्यों, सड़कों, रेल लाईनों आदि को रोक कर रखा। भूमि-अधिग्रहण कानून, सीएनट-एसपीटी कानूनों में संशोधन आदि के खिलाफ जनांदोलनें हुईं। हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए ने जनता की सक्रिय भागीदारी से अंजाम दिये गये कई साहसिक गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों में सरकारी भाड़े के सशस्त्र बलों को उल्लेखनीय संख्या में नुकसान पहुंचाया। इसी क्रम में यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान लगभग 490 क्रांतिकारियों और 745 आम जनता पुलिस की झूठी मुठभेड़ों, जनसंहारों और मुठभेड़ों में अपने जान गवाएं। पुलिस बलों ने कई गांव और सैकड़ों घरों को जला दिया और 'उपा' जैसे दमनकारी कानूनों के तहत हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया। 100 से ज्यादा आदिवासी युवातियों पर अत्याचार कर उनमें से कइयों की हत्या की। हजारों लोगों को क्रूर यातनाएं दी। इस दमन के बारे में

सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रयासरत पत्रकारों, लेखकों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला व आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर षड़यंत्रकारी मामले लगाकर जेल में ठूंस दिया। इसके बावजूद, इन ज्वार-भाटों का सामना करते हुए हमारी पार्टी ने सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध को जनांदोलनों के साथ समन्वय करते हुए देश में जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप, साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के देश-विदेशी कम्पनियों द्वारा केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ किये गये अधिकतर व्यापार और औद्योगिक समझौते लागू नहीं हो पायीं। इसके बाद सरकार अपनी दमनकारी रणनीतिक को समीक्षा की और 8 मई 2017 को 'समाधान' रणनीति की घोषणा देश की राजधानी दिल्ली में की। इसके लिए पांच साल (2017-22) समयावाधि तय की गई।

केन्द्र में मोदी सत्ता में आने के तुरंत बाद सभी सामाजिक क्षेत्रों में अपने आक्रमकता स्पष्ट रूप से दर्शाया। 2014 लोकसभा चुनाव में उन पर हजारों करोड़ पैसे खर्च कर उनको सामने लाने वाले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हितों के अनुरूप जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में बदलावों को लागू किया। हम सब भलीभांति जानते हैं कि मोदी की मातृ संस्था आरएसएस है और उनका आदर्श हिंदू-राष्ट्र की भावना की सृजन वाले श्रीगुरूजी (गोलवलकर) है। उनके अत्यंत नजदीकी अनुयायी है अमित शाह। मोदी के बाद शासन के अधिकार अधिकतर अजीत डोबल हाथों में है। मोदी ने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतर शासन' की सिर्फ लफ्फाजी करते हुए व्यवहार में पूरी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रीकृत किया और व्यापार, वाणिज्य, बीमा, रक्षा आदि क्षेत्र में उनके द्वारा लिए गए हरेक कदम में देश-विदेशी कार्पोरेटों का संकट की भार कम करने और उन्हें सुपर मुनाफे पहुंचाने के लिए प्रयास किया। मोदी-शाह-भागवत गुट के नेतृत्व में ललित मोदी, विजय माल्य, नीरव मोदी जैसे कुख्यात कार्पोरेट घरानों को सुरक्षित देश सरहदों से पार करने से लेकर राफेल युद्ध विमानों की खरीदी में कार्पोरेट कुबेर अनिल अंबनी को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होने तक; जन-धन योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक; प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से लेकर एनपीए (निरर्थक संपत्ति) के नाम पर कार्पोरेट कम्पनियों द्वारा लिए गए ऋणों का रफा-दफा करने तक; नोटबंदी, जीएसटी आदि कई कदमों और नीतियों को लागू कर जनता के पैसे कार्पोरेट घराने वर्गों को पहुंचाने तक कई घोटाले हुई। इस गुट के नेतृत्व में देश में

संस्कृतिक तौर पर राममंदिर निर्माण से लेकर सबरीमला मामले तक; विभिन्न शहरों के पुराने नाम बदलकर हिंदू धर्म के नाम रखने तक; पर-धर्म सहिष्णुता घट जाने की वजह से गोरक्षा, लव जिहाद से लेकर घर वापसी तक; कश्मीर और उत्तर-पूर्व राष्ट्रीयताओं के जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने से लेकर संविधान का भी उल्लंघन कर कश्मीर में आग लगाने और आसम में नागरिकता संशोधन कानून 2016 के नाम पर जनता के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करने तक ब्राह्मणी हिंदू फासीवाद की विस्तार हुई। वह गलत आंकड़ों और काल्पनिक कथनों के साथ जो नहीं किया किया जैसा, जो हासिल नहीं हुआ हासिल हुआ जैसा बड़े पैमाने पर उन्मादपूर्ण प्रचार कर रही है। देश के अंदर इस गुट के नेतृत्व में लागू ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ सामने आने वाली सभी तरह के आंदोलनों, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह उन्मूलन करना साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और देश के उनके दलाल के रूप में रहे दलाल नौकरशाही पूंजीपति और बड़ा सामंती वर्गों के लिए बहुत जरूरी है। इस बड़े योजना के तहत ही वर्तमान 'समाधान' रणनीति को सामने लायी गयी है।

'समाधान' की रणनीति तय करने में राष्ट्रीय सुरक्षा मंडल के सलाहकार अजीत डोबल और आंतरिक सुरक्षा के पूर्व सलाहकर के विजय कुमार ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। धनाढ्य शक्तियों, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्रों सहित 'संस्कृति राष्ट्रवाद' तक प्रशिक्षण देनेवाली विवेकानंदा फाउंडेशन को संचालित करने वाले डोबल आरएसएस के लिए अत्यंत करीबी माना जाता है। उन्होंने रक्षा, गृह, विदेशी और आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ नीति आयोग और रीजर्व बैंकों का भी निर्देशन दे रहे हैं और रक्षा योजना समीति के अध्यक्ष तथा हाल ही में पुनर्व्यवस्थित रणनीतिक नीति समूह के प्रमुख भी है।

'समाधान' रणनीतिक को घोषणा करने के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों का आक्रमकता में बहुत वृद्धि देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में जून 2017 से दिसंबर 2018 तक सिलसिलेवार ऑपरेशन प्रहार 1, 2, 3 और 4 को संचालित किया गया है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक-तमिलनाडु-केरलम के ट्राइजंक्शन इलाका, पश्चिम बंग और असम के हमारे आंदोलन के इलाकों में अलग-अलग नामों से लगातार ऑपरेशन संचालित किया गया। छत्तीसगढ़ में हर ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया। गांवों, घरों और जनता की सम्पत्ति

को ध्वस्त किया गया। केन्द्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता में जो भी पार्टी हो, क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में सभी सरकार एकजुटता दर्शा रही है। वर्तमान केंद्र और विभिन्न राज्यों में मोदी नेतृत्व वाली हिंदू फासीवादी गुट सत्तासीन है और माओवादी विरोधी क्रूर 'समाधान' हमले को नेतृत्व कर रही है। लेकिन विभिन्न राज्यों में गैर-भजपीय सरकार - ओड़िश में नवीन पटनायक, तेलंगाना में केसीआर, आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू, पश्चिम बंग में ममता बेनर्जी, बिहार में नीतिश, केरल में पिनाराई विजयन, तमिलनाडु में पलानी स्वामी, कर्नाटक में कुमार स्वामी सत्ता में होने के बावजूद, इस ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी गुट के साथ हाथ मिलाकर क्रांतिकारी आंदोलन पर फासीवादी हमले जारी रखने में होड़ में लगी हुई हैं।

'समाधान' रणनीति के अनुसार, क्रांतिकारी आंदोलन जहां जारी है उन सभी राज्यों में विशेष पुलिस व अर्धसैनिक बलों के कैम्प यानी कार्पेट सेक्युरिटी को और मजबूत व विस्तारित की जा रही है। मई 2017 से दिसंबर 2018 तक छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके, राजनंदगांव और कबीरदाम जिले; महाराष्ट्र में गढ़चिरोली और गोंदिया जिले; ओड़िशा में कंधमाल से लेकर नुआपाड़ा तक के जिले, मलकानगिरी और कोरापूटा जिले; आंध्र प्रदेश में विशाखपट्टनम और विजयनगरम जिले; तेलंगाना के खम्मम जिले; मध्य प्रदेश के बालाघाट और मांदला; बिहार और झारखंड के आंदोलन के समस्त जिलों को मिलाकर लगभग 100 तक नये पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कैम्प लगाए गए हैं। हलांकि, पश्चिमी घाटियों के कर्नाटक-तमिलनाडु-केरलाम ट्राइजंक्शन के आंदोलन के इलाके में अभी तक अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं किया गया है, इसके बावजूद वहां के भौगोलिक सर्वे से लेकर समय-समय पर तीन राज्यों के पुलिस द्वारा संचालित सभी संयुक्त छानबीन अभियान उनकी ही मार्गदर्शन में हो रही हैं। इस तरह देशभर में माओवादी आंदोलन के इलाकों में जंगलों और मैदानों को अर्धसैनिक और कमांडों बल द्वारा नाकेबंदी की जा रही है।

'समाधान' रणनीति के तहत ही मई 2017 और दिसंबर 2018 के बीच क्रांतिकारियों पर कई सूचना आधारित अभियान संचालित कर भारी जनसंहारों को अंजाम दिया गया है। दंडकारण्य के इरपानार (माड़), पूजारी कांकेर (तेलंगाना), कसनूर-तुमीरगुंडा (गढ़चिरोली), आयपेटा, तिम्मेम (बीजापुर), गुमयावेड़ा (माड़), ओड़िशा के मलकानगिरी में पप्पुलूर जैसे कई घटनाओं में, झारखंड के चतरा और गिरीडीह जिलों में कुछ जगहों पर गुरिल्ला दस्तों पर

पुलिस अंधाधुंध गोलीबारी कर 190 क्रांतिकारियों और 95 आम जनता की हत्या की गयी है। व्यापक इलाके में विध्वंस मचाने वाले यूबीजीएल जैसे इलाकायी (भारी) हथियार, मोर्टार और रॉकेट लांचारों को सभी मुठभेड़ों में अंधाधुंध इस्तेमाल किया रहो है। घायल होने के बपद अपनी गिरफ्त में आने वाले साथियों को बेहद यातनाएं देकर मारा जा रहा है। निहत्थे अपने गिरफ्त में आने वाले गांव वालों को भी डंडा और पत्थरों से पीट-पीट कर यातनाएं देने के बाद अमानवीय ढंग से हत्या की जा रही है। हाल ही में राजनंदगांव जिले में तीन गुरिल्ला योद्धाओं (संजय, विनोद, आजाद) को क्रूर तरीके से हत्या की है। गढ़चिरोली में क्रांतिकारी जनताना सरकार के अध्यक्ष सोनसाय को जिंदा जला दिया गया है।

वर्तमान माओवादी आंदोलन के इलाकों में 5,57,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। 'समाधान' हमले से पहले इनकी संख्या 5,20,000 तक थी। इसके बाद और 37,000 बलों को तैनात की गई है। 2016-17 तक हर साल खुले तौर पर गृह मंत्रालय के रिपोर्टों में बलों की तैनाती का ब्यूरा दी जाती थी। लेकिन 'समाधान' हमला शुरू होने के बाद इस ब्यूरा गुप्त रखी जा रही है।

आंदोलन के इलाकों में यह बल लगातार सर्च कार्रवाई करते हुए, हर रोज जंगल में घूमने वाले आदिवासियों को घेराव कर गिरफ्तार कर रहे हैं। अपनी आत्मरक्षा के लिए साथ रखने वाले पारम्पारिक हथियारों को भी जब्त कर रहे हैं। उन्हें कई अवैध मामलों के फंसाकर थाना और कोर्ट घुमाते हुए सलाकों के पीछे ठूंस रहे हैं। उनमें से कोई भी पुलिस को प्रतिरोध करने से उन्हें लापता कर हत्या कर रहे हैं या खुलेआम फर्जी मुठभेड़ों में मार रहे हैं। 19 अप्रैल को ओड़िशा के नुआपाड़ा जिला के बोड़ेन थाना क्षत्र के कुयीमुंडा गांव के पूर्व सरपंच सुकालसाय पहारया को लापता कर हत्या की। उनकी शव 52 दिनों के बाद 10 अक्टूबर को भैंसाधानी नदी में फेंक दिया।

जंगलों में पुलिस की छानबीन काईवाइयों में खुद बारूदी सुरंगों को रखकर सर्च अभियान में मिलने की दावा करते हुए, उन्हें विस्फोट कर जनता के अंदर आतंक मचा रहे हैं। क्रांतिकारियों को मारने के लिए लागू की जाने वाली कई षड्यंत्रों के तहत उन्हें जहर दिलाने के लिए गांव-गांव में गलत तत्वों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब इस खतरा बढ़ रही है। अवैध गिरफ्तारियां उनके द्वारा जारी की गयी आधिकारिक आंकड़े से कई गुणा अधिक होती है। झूठी आत्मसम्पर्ण दसियों संख्या में दिखा रहे हैं। इन झूठे आंकड़ों को लेकर अब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान सभाओं में ही नहीं, बल्कि स्वयं प्रध

ान मंत्री मोदी द्वारा भी 'समाधान' रणनीति की महत्व को दर्शाने के लिए घोषित करना शुरू हो गई है।

देश में गरीबी उन्मूलन के लिए, सभी लोगों को स्वास्थ बनाने के लिए, हर आदमी को साक्षर बनाने के लिए समय-समय पर देश की नेताओं द्वारा समयसीमा जिस तरह घोषणा की जाती है, उसी तरह एक बार 2018 की विध ान सभा चुनाव तक, और एक बार 2019 की लोकसभा चुनाव तक छत्तीसगढ़ माओवादी विहीन राज्य हो जाने की दावा मिशन-2016 और मिशन-17 के दौरान ही बहुत ही धूमधाम से घोषित की गयी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पायी। वर्तमान 'समाधान' रणनीति के लिए समयसीमा (2017-22) रखा गया है। लेकिन 2018 के शुरूआत में जनप्रतिरोध तेज हो जाने के कारण केन्द्रीय गृह मंत्री अपने दावा को बदलते हुए 'यह समयसीमा बदल भी सकती है' बताया। इस तरह समयसीमा अपनी साम्राज्यवाद मालिकों को खुशी करने, उनसे अतिरिक्त पूंजी आकर्षित करने और पहले ही लगायी गयी पूंजी को कायम रखने के लिए निर्धारित करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। वास्तव में वे भी जानते हैं कि उस तरह की कोई भी समयसीमा लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं हैं। जो लोग नक्सलबाड़ी क्रांतिकारी आंदोलन की इतिहास के बारे में जानते हैं उनको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं हैं। उन्होंने इस तरह की बहुत ही समयसीमाओं को देख चुके थे। दरअसल आंदोलन में ज्वार-भाटे होती हैं, उसके बजाय जितने भी 'समाधान' हमले सामने आने के बावजूद उसकी अंत नहीं होगी।

माओवादी आंदोलन के इलाकों में तेज गति से प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए और सरकारी की भाड़े की सशस्त्र बलों को जल्द तैनात करने के लिए सैकड़ों करोड़ रूपयों को खर्च कर रोड़, रेल लाइन और हवाई अड्डे जल्द निर्माण करना 'समाधान' रणनीति में बुहत ही महत्वपूर्ण पहलू हो गयी है। इसके लिए पैसा की कोई कमी नहीं होने की भरोसा दिलाते हुए चौड़ी सड़कों और राष्ट्रीय राजगार्म निर्माण किया जा रहा है और सड़कों को चार से लेकर 16 लेन तक विस्तारित की जा रही है। इनके निर्माण के लिए ही विशेष तौर पर अर्धसैनिक और कमांडों बलों को तैनात की गयी है। ठीक इसी कारण ही क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों के जनता सड़कों का निर्माण को तीव्र रूप से विरोध कर रहे हैं, पहले ही निर्मित और अभी निर्माण किये जानेवाले सड़कों को बार-बार ध्वस्त कर रहे हैं। देश-विदेशी कार्पोरेट कम्पनियां देश की संसाधनों की

दोहन के लिए निर्माण किये जानेवाले इस तरह के बुनियादी सुविधाओं को जनता क्यों विरोध कर रहे हैं इसके बारे में जनहितैषियों और देशभक्त जानना बहुत जरूरी है और जनता की बुनियादी समस्याओं हल करने के नाम पर लुटेरी सरकार द्वारा दी जाने वाले इस तरह की 'समाधान' को ठुकरा देना चाहिए।

'समाधान' रणनीति की घोषणा के बाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रधान करनेवाले हमारे पार्टी के नेतृत्व को पहले से मुकाबले बहुत अधिक निशाना बनाते हुए लुटेरी सरकारें दुष्प्रचार कर रहे हैं। एनआईए भी इसमें शामिल हो गयी है। नेतृत्वकारी फोटो, उनकी गतिविधियों की ब्यूरा, कार्यक्षेत्र की ब्यूरा, खान-पान के नियम, उम्र, बुढ़ापा और अस्वास्थ्यता के बारे में तोड़-मरोड़ कर पेश करते हुए, गलत 'हाई प्रोफाइल' बयोडेटा बनाकर कार्पोरेट मीडिया में पहुंचा रहे हैं। मीडिया इस ब्यूरा को सनसनी खबर के रूप में बदलकर खूब कमा रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर कमजोर तत्वों को आत्मसम्पर्ण कराने के लिए नयी-नयी वादा और आकर्षणीय पुनर्वास योजना सामने ला रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हाल ही में केन्द्रीय सूचना मंत्रियों द्वारा घोषणा की गई है कि माओवादी आंदोलन के इलाके से संबंधित दस राज्यों के 96 जिलों में पहली चरण में 2,356 मोबइल टॉवर का निर्माण हो चुकी है और अगले दो साल में लागू होने वाली दूसरी चरण में और 4,072 मोबइल टॉवर निर्माण किया जायेगा। एक-एक टॉवर निर्माण के लिए न्यूनतम एक करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च होगी। इसके अलवा, लाखों संख्या में मोबइल फोन मुफ्त बांट रहे हैं। लेकिन वास्तव में पुलिस जानते हैं कि ह्यूमान इंटलिजेन्स के बजाय अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इसलिए गद्दारों, प्रतिक्रियावादी और लम्पट तत्वों को कई प्रालोभन देकर, बड़े पैमाने पर पैसे पहुंचाकर उनके साथ मुखबीर तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। उनकी सूचना के आधार पर हमले कर रहे हैं। जनता की समस्याओं का हल के लिए यही उनकी 'समाधान' है। देश में बड़े पैमाने पर फैल रही बेरोजगारी समस्या के लिए यही उनकी 'समाधान' है।

मिशन-2016 में ही 'शहरी माओवादी' के खिलाफ लड़ने के लिए अग्नी (एक्शन ग्रुप फार इंटीग्रेशन) संगठन को सामने लाने के बावजूद देशभर में जनविरोध की उभार की वजह से वह दुम दबाकर पीछे हट गई। लेकिन वर्तमान 'समाधान' हमले के तहत, मोदी-शाह-भागवात के गुट ने योजनाबद्ध ढंग से अजीत डोबल की देखरेख में षड़यंत्रकारी तरीके से दलित, मानवाधिकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर 'शहरी माओवादी' के नाम पर देशभर में एक ही बार

हमला किया। कार्ल मार्क्स द्वारा 1848 में ही 'यूरोप में एक भूत फैल गई, वह है कम्युनिस्ट भूत' की व्याख्या करने की 170 साल की बाद, फिर से वह भूत माओवादी भूत के रूप में भारत में फैल जाने की वजह से शासक लोगों को नींद हराम हुई। इसलिए उन्होंने एकाएक 'शहरी माओवादियों' पर एक षड़यंत्रकारी मामले थोप दिया कि वे देश के प्रधान मंत्री मोदी को ही हत्या करने जा रहे हैं, तमिल टाइगर जिस तरह राजीव गांधी को हत्या की, उसी तरह मोदी को मारने की योजना बना रहे हैं।

विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में जनता के लिए अपनी सेवा करने वाली प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता कामरेड्स सुधीर धावले, सोमासेन, सुरेंदर गाडलिंग, रोना विलसन और महेश राउत को जून महीने में, इसके बाद कामरेड्स वरवरराव, गौतम नवलखा, वरनान गोंजालविस और सुधा भरद्वाज को अगस्त महीन में गिरफ्तार किया गया। गौतल नवलखा को छोड़कर अन्य लोगों पर क्रूर कानूनों के तहत मोदी की हत्या सहित कई गलत मामले थोप पर सलाकों के पीछे ठूंस दिया गया। उनकी बिनाशर्त रिहाई के लिए देश और दुनिया के श्रमिक संगठन, प्रमुख बुद्धिजीवि, मानवाधिकार कार्यकर्ता, आखिर यूरोपीय संसद के सदस्य और कई नोबेल पुरूष्कार ग्रहिताओं ने आंदोलन किये। लेकिन हिंदू फासीवादी गुट ने और एक बार कई लोगों को उसी तरह किसी क्षण में बंदी बनाने के लिए योजना तैयार कर चुकी है। लगभग 300 जनसंगठन के प्रतिनिधित्व के साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी.वी. सावंत के अध्यक्षता में बनायी गयी 'एलगर परिषद' के नेतृत्व में 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव के अमर शहीदों के याद में 200वीं स्मृति दिवस पालन करना और 'नयी पेशवायी, नहीं चलेगा' के नारा देना ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी तत्वों ने हजम नहीं कर पाये। यह वर्तमान में हिंदुत्व शक्तियों द्वारा प्रास्तावित 'नया भारत' का पूरा खिलाफ है। जनता की समस्याओं का हल के लिए, विशेषकर दलित, आदिवासी और मुसलिम अल्पसंख्याकों में बढ़ती आक्रोश के लिए यही उनका 'समाधान' है।

इस तरह 'समाधान' रणनीति के तहत देश में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी शक्तियों ने अपने रास्ते में रोड़ा बने हुए देशभक्त, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, सामाजिक और क्रांतिकारी शक्तियों को हटाने के लिए अपने हमले केन्द्रित किये हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में हो; दंडाकारण्य, सारंडा, पश्चिमी घाटियों, कनहा, भौरमदेव, नियमगिरी, गंधमर्धन हो; पूणे, कोलहापुर, बंगलूरु, हैदराबाद, विशाखापटनम,

रायपुर, नागपुर, गढ़चिरोली, दिल्ली में हो; वे जंगल हो या मैदान हो, या विश्वाद्यालय हो; भीमा कोरेगांव जैसे बड़े जनसमूह ही क्यों न हो; नरेंद्र दभोलकर, गोविंद पंसरे, एम.एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश जैसे धर्मनिरपेक्ष ताकत ही क्यों न हो; अग्नीवेश गांधीवादी ही क्यों न हो ... देश के किसी भी भूभाग में हो, किसी भी रूप में हो – अपने रास्ते में उनकी अवरोध हटाना चहती हैं ... साम, धान, भेद और दंड नीति को अपनाकर उन्हें आत्मसम्पर्ण कराने चहती हैं। जेलों में ठूंसते हैं या भौतिक रूप से सफाया कर देती हैं या जेएनयू नजिब जैसा लापताकर देती हैं। इसके लिए उन्होंने संविधान हो या किसी भी कानून हो उसका संशोधन करती हैं और नया कानून बनाती हैं ऐसा संभव नहीं तो अध्यादेश जारी करते हैं। देश की जनता के समस्याओं के लिए उनकी 'समाधान' द्वारा यही रास्ते दर्शाये जा रही हैं।

वे अपनी रणनीतिक योजना के तहत ही सिर्फ माओवादियों को ही नहीं बल्कि सत्तासीन हिंदू फासीवादी गुट के खिलाफ लड़ने वाली जनवादी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और देशभक्त शक्तियों को भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि साम्राज्यवाद प्रायोजित नयी उदारवादी नीतियों को तेजगति से अमल करते हुए मोदी सरकार नयी दमनकारी श्रम कानूनों को बनायी है। सभी क्षेत्रों में एफडीआई को पूरी तरह अनुमति दे दी है। कृषि क्षेत्र को कार्पोरेट कम्पनियों का हवाला कर उस क्षेत्र में संकट और तेज किया है। देश-विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित भारी प्रोजेक्टों, बांधों, प्लांटों जैसे परियोजनाओं के वजह से लाखों आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता विस्थापित हो रहे हैं। 'मेन इन इंडिया' 'मुद्रा योजना' 'स्टार्टप', 'स्टेंडप' 'स्किल इंडिया' योजनाओं द्वारा रोजगार-विहीन वृद्धि के बजाय बेरोजगारी समस्या हल नहीं हुई है। हिंदू फासीवादी ताकतों के बल पर शिक्षा को निजीकरणा-भगवाकरण, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की हनन, विश्वविद्यालयों में छात्राओं पर पितृसत्तात्मक पाबंदियां लगाना तेज हो गयी है। फलतः मजदूरों, किसानों, बेरोजगारी, छात्र-युवा, विभिन्न प्रोजेक्टों के वजह से जनता और महिलाओं ने तीव्र आक्रोश के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़नेवाले हरेक आदमी के पीछे मोदी सरकार 'माओवादी लिंक' खोज रही है।

हिंदुत्ववादी तत्व हिंदुओं के लिए गाय पवित्र ठहराते हुए उसे राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित की है। गोमांस खाना प्रतिबंधित की जा रही है। खुलेआम आतंक फैलाते हुए दलित, आदिवासी और मुस्लिमों को पीट-पीट कर मारा जा

रहा है। मुस्लिम लोगा 'भारत माता जय' बताना से इंकार करने पर, इस देश छोड़कर पाकिस्तान जाने की हिदायत दिया जा रहा है। पिछले चुनावों में किए गए वादे पूरा नहीं करने, मोदी सरकार की सभी योजनाएं खोखले और आंशूपोंछ कदम साबित हो जाने के कारण, हिंदू फासीवादी ताकतों द्वारा धर्म के आधार पर तेजी से देश को ध्रुवीकारण कर लोकसभा चुनावो में फिर से सत्ता हासिल करने की साजिश रची जा रही है। वे हिंदू धर्मांधता को इतना बढ़ा रही है कि राम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए देवता है, अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए कोर्ट की फैसले की कोई जरूरत नहीं है और खुद जनता राममंदिर का निर्माण कर सकते हैं। वे पाकिस्तान को सीमांतर उग्रवाद, उग्रवाद की उत्पादक और निर्यातक और बाहरी दुश्मन ठहराते हुए, विश्व के मंचों पर अपनी राष्ट्रीय उन्माद उगला रहे हैं। वे आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान के बल पर ही कश्मीर द्वारा आत्मनिर्णय की अधिकार मांग की जा रही है। राष्ट्रीताओं को अलग होने के साथ-साथ आत्मनिर्णय की आधिकार के लिए, अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर लड़ने वाली सभी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का 'अखण्ड भारत' के नाम पर कुचला जा रहा है। कश्मीर के लिए स्वायत्तता प्रदान करने वाली धारा 370 और धारा 35ए उनको हजम नहीं हो पा रही है। देश के विभिन्न राष्ट्रीयताओं को निरंकुश तरीके से कुचलकर, देश में शामिल करने वाले सरदार पटेल की मूर्ति को विश्व में ही अत्यंत ऊंचाई से प्रतिष्ठित कर, उन्हें लौहपुरूष और उनकी मूर्ति को 'एकता मूर्ति' ठहरा रहे हैं। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत; 'वन नेशन-वन पोल'', 'वन नेशन-वन टैक्स' आदि सभी उनका हिंदू-राष्ट्र का निर्माण की दिशा में धोखेबाजी कदम हैं और 'नया भारत' की रणनीति में अभिन्न अंग है। इनकी अगुवाई करती है, उनकी इस 'समाधान' रणनीति।

इसलिए, उनकी इन विध्वंसकारी रणनीतिक योजनाओं को हराने के बजाय इस देश को हिंदुत्ववादी ताकतों के हमलों से बचा नहीं सकते हैं; संसदीय जनवाद के स्थान पर जनता की जनवाद का कभी निर्माण नहीं कर सकते हैं एवं साम्राज्यवादियों के आर्थिक और राजनीतिक श्रृंखलाओं के वजह से दशकों से अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती देश के रूप में जूझ रहा भारत में सच्ची जनवाद और स्वावलंबन के आधार पर भारत की जनता के जनवादी गणराज्यों की संघ के रूप में स्थापित नहीं कर सकते हैं। अपने जायज मांगों के लेकर लड़ रहे मजदूरों; सैकड़ों संगठनों में संगठित होकर 'किसान संसद', 'महारैली'

जैसे संघर्ष तरीके अपनाकर आगे आए हुए किसनों; दलितमुक्ति के लिए लड़ रहे विभिन्न दलित संगठनों और शक्तियों तथा अन्य धर्मनिरपेक्षों; जल-जंगल-जमीन-इज्जत-अधिकार के लिए आदिवासी इलाकों में ग्रामसभाओं (पत्थलगड़ी) में, क्रांतिकारी इलाकों में क्रांतिकारी जन कमेटीयों (आरपीसी) में संगठित होकर लड़ रहे मूलवासियों; छात्रों, कर्मचारियों, महिलाओं, मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंद शहर तक और उना से लकर अल्वर तक हिंदुत्ववादी तत्वों के हमलों में सिलसिलेवार नुकसान झेल रहे मुस्लिम और दलित जनता; अलग होने सहित राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय अधिकार के लिए लड़ने वाली विभिन्न राष्ट्रीताओं; ब्राह्मणीय उच्च-जातियों के दबदबे और शोषक वर्गों को विरोध करने वाले सभी लोगों के लिए यह सही समय है कि एकजुट होकर संघर्ष किया जाय। इसलिए इस समय देशभक्त, धर्मनिरपेक्षों, जनपक्षदर पत्रकारों, लेखकों, कवियों, कलाकारों, वकीलों, जनवादीप्रेमियों, प्रगतिशील शक्तियों व व्यक्तियों का हमारी पार्टी कां अपील है कि पहले के मुकाबले दृढ़ता, स्थिरता और तीव्र रूप से संघर्ष किया जाय और मोदी-अमित शा-भागवत के गुट द्वारा लागू हिंदू फासीवादी नीतियों के खिलाफ देशभर में व्यापक जन आंदोलन को विकसित करने, 'नया भारत' का निर्माण के तहत 'समाधान' की दमनकारी रणनीति के पीछे छिपी हुई सभी सच्चाइयों को देश की जनता के सामने भण्डाफोड़ किया जाय। उत्पीड़ित जनता को, विशेषकर ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद विरोधी सभी शक्तियों को हमारी पार्टी का अपील है कि 25-31 जनवरी तक 'समाधान' हमले विरोधी सप्ताह और 31 जनवरी को 'भारत बंद' को सफल बनाया जाय।

- ✶ 'समाधान' रणनीति को हराएं, जनवादी, क्रांतिकारी और राष्ट्रीयमुक्ति आंदोलनों बचाएं!
- ✶ साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति औ बड़े सामंति वर्गों को सेवा करने वाली है 'नया भारत'!
- ✶ भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में बदलने वाले 'नया भारत' को विरोध करें!
- ✶ सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक बंदियों बिनाशर्त रिहाई की मांग करें!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

केंद्रीय कमेटी

20 दिसम्बर 2018 **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**

✶